



PG,5

आधुनिक समाचार

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

आधुनिक भारत का आधुनिक नजारिया



PG,8

वर्ष -07 अंक -342

प्रयागराज, गुरुवार 17 फरवरी, 2022

पृष्ठ- 8 मूल्य : 2.00 रुपये

संक्षिप्त समाचार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान गलत

नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को खारिज कर दिया। दरअसर मुख्यमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी बोली आयोजित करता तथा उसके आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने को स्वतंत्र है। बिजली और नेटवर्क एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के 11 फरवरी को नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के स्वतंत्र है। उन्होंने अपने सबोधन में कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों पर विशेष कानूनों से अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए दबाव डालती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आर के सिंह के बाले से बताया 'यह पूरी तरह गलत है।' बयान के अनुसार, राज्य खर्च से बोलिया रखने और उन बोली से अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए स्वतंत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र की सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सेक्टी) भी समय समय पर नवीकरणीय ऊर्जा का लिये बोलियां आमंत्रित करती है।

असम के शहरों कर्सों और गांवों के नाम बदलने पर सरकार कर रही है विचार

गुगाहाटी। शहरों, कर्सों और गांवों के नाम बदलने की प्रणा से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में धौर्मिक और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर शहरों के नाम बदलने के बाद, देश के अन्य राज्यों में यह कल्पना शुरू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार शहरों, कर्सों और गांवों के नाम बदलने पर लोगों के सुझाव लेगी, जिसके लिए एक पाठल शुरू किया गया है। बताए गए विपरीत और किसी भी जाति या समुदाय के लिए 'अपमानजनक' है। हैंडल से आज सुबह एक ट्रॉट कर कहा कि राज्य हर शहर, कर्सा या गांव का नाम उसकी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

बंगाल में आज से खुल रहे हैं स्कूल, कोविड प्रोटोकाल के अनुसार हो चुकी तैयारी

कोलकाता। कोविड-19 कोलाइनी को कम होता देख देश के अधिकांश राज्यों की तरह बंगाल, राजस्थान व तमिलनाडु में बुधवार से सभी प्राइमरी व अपर

पीएम मोदी ने करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर टेका माथा, 'शबद कीर्तन' में लिया भाग

नई दिल्ली। देशभर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र



मोदी करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचा।

रविदास की बानाना को आत्मसत्

किया है संत रविदास जयंती के मौके पर करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा की।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और

रविदास

विश्राम धाम मंदिर में दुग्धा था।

पीएम ने ये भी क

सम्पादकीय

दुनिया में वही समाज
आगे बढ़ता है, जो समय
के साथ प्रतिगामी प्रथाओं
का परित्याग करता है

कर्नाटक के उडुपी शहर के एक सरकारी स्कूल से उभरे हिजाब विवाद को इस रूप में पेश करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और शरारत की जा रही है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर आफत आ गई है। जिन दिनों यह विवाद सुलगा रहा था, उन्हें दिनों यानी इसी 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक फैसले का संज्ञान लेना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि एक तो वह देश के सबसे लघु या कहें कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग-पारसी समुदाय से जुड़ा है और दूसरे इसलिए भी कि उससे यह पता चलता है कि परिवर्तन एवं प्रगतिशील समाज किस तरह देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पुरातन-प्रतिगामी परंपराओं में परिवर्तन करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसी समुदाय की आबादी कीरीब 57 हजार है। 1941 में उनकी आबादी 1.14 लाख थी। पारसियों की आबादी तेजी से बढ़े, इसके लिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय 'जियो पारसी' नाम से एक योजना चला रहा है। इस योजना के चलते 2020 में जब यह आंकड़ा सामने आया कि पारसी समुदाय में 61 बच्चों का जन्म हुआ तो इसे एक उपलब्धि माना गया, लेकिन आज विषय यह नहीं कि यह योजना कितनी प्रभावी है? विषय यह है कि जब कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार को लेकर प्रोटोकाल जारी हुआ तो मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में सीमित पारसी समुदाय के सामने संकट खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया, क्योंकि यह समुदाय अपने लोगों के शरू को एक ऊंची मीनार की छत पर रख देता है ताकि कौए, गिर्द आदि उसका भक्षण कर लें और जो अवशेष रहे, वह सूर्य की गर्मी से सूख जाए। इस तरह की मीनार का 'टावर आफ साइलेंस' कहते हैं। कोरोना काल में यह खतरा उभर आया कि अगर कोविड से मरे किसी पारसी के शरू को पक्षी खाएंगे तो वे संक्रमण पैलाएंगे। इसलिए गुजरात प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। पारसी समाज के लोग गुजरात हाईकोर्ट गए। वहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली तो वे सुप्रीम कोर्ट आए, बिना यह शोर मचाए कि उन पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार दिया। इस टिप्पणी के पक्ष और विपक्ष में विचार आने स्थाभाविक है। सवाल है कि किन कसौटियों पर असली समाजवादियों की पहचान की जाए इस देश में समाजवाद के मुख्यत तीन प्रतीक पुरुष रहे हैं—आचार्य के लिए चुने गए थे। उनमें आचार्य नरेन्द्र देव भी थे। आचार्य और विधायकों ने नैतिकता के आधार पर विधानसभा की सदस्यता भंग छोड़ दी। वैसे इस्तीफा देने के संवैधानिक मजबूरी नहीं थी। ताकि दलबदल विरोधी कानून भी नहं था। इन लोगों ने उपचुनाव लड़ाए को छोड़कर आचार्यी सहित

रोकना चाहिए। इन दिनों तो ऐसी
बुराइयों के कारण राजनीतिक दल
एक-एक कर मुरझाते जा रहे हैं।
इसके बावजूद उन दलों को इसकी
कोई परवाह नहीं। संसद सदस्य
रहने के बावजूद लोहियाजी ने कार
नहीं खरीदी। वह कहते थे कि कार
की साज़-संभाल लायक मेरी आय
नहीं है। वह यह जान गए थे कि

घोटाले में फूब जाएगा। मुलायम सिंह यादव लोहियाजी केरे जीवनकाल में ही यानी 1967 में विधायक बन चुके थे। भले ही आज के समाजवादी नेता लोहियाजी की शैली से अनन्जान हों, लेकिन मुलायम ने उनकी जीवन शैली और राजनीतिक शैली को काफी ज़दीकी से देखा था। लोहियाजी का नारा

थे। उनके जितने भी निजी सचिव हुए, सबके सब ब्राट्सूण थे। आज के समाजवादी नेता जातीय-सांप्रदायिक वोट बैंक के किले में सुरक्षित हैं। लोहियाजी ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी छोड़ देने को कहा था कि जिसकी ढुकान में शराब बिकती थी। रांची के उस व्यक्ति ने शराब का व्यापार छोड़ दिया। आजादी के बाद जगहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण से सरकार चलाने में सहयोग देने की अपील की। दरअसल वह चाहते थे कि जेपी उनकी सरकार में शामिल हों। इस पर जेपी ने नेहरूजी को अपनी 14 सूचीय मांग की सूची थामा दी। उसमें निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भी मांग थी। नेहरूजी ने कहा



नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डा. राममनोहर लोहिया। इन तीनों की जीवनशैली, चाल, चरित्र और चिंतन की कसौटी पर आज के समाजवादियों को आसानी से कसा जा सकता है। आज के समाजवादी इन हस्तियों का यदाकदा नाम लेते रहते हैं, पर उनका कितना अनुसरण करते हैं, इसे देखा जाना चाहिए। ये तीनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में प्रमुख थे। आजादी की लड़ाई के दिनों में ये और इनके अनुयायी एक साथ कांग्रेस में भी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी। आजादी के तलाल बाद कांग्रेस ने इन समाजवादियों से कहा कि या तो आप लोग कांग्रेस में शामिल हो जाइए या फिर उसे छोड़ दीजिए। एक साथ दो जगह नहीं रह सकते। नीतीजतन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस का त्याग करके सोशलिस्ट पार्टी बना ली। इसके पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 13 सदस्य कांग्रेस के टिकट पर 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सभी हार गए। आचार्यजी से कनेताओं ने कहा था कि कांग्रेस का अब भी हवा है। उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे, किंतु उनके लिए जीत-हार से अधिक नैतिकता प्रिय थी। उपचुनाव में उनके क्षेत्र में यह प्रचार किया गया कि वह नास्तिक है, इन्हें गोट मत दीजिए। आचार्य जैन ने इस का खंडन नहीं किया, क्योंकि वह नास्तिक ही थे। उनके प्रतिद्वंद्वी बाबा राधवदास ने उन्हें हरा दियारा किया था कि वही हस्ती थे, जिन्होंने नेहरूजी के कहने पर इदिरा टे बैटों का नामकरण किया था-राजी और संजय। उन्होंने नेहरूजी को किताब 'डिस्कर्वरी आफ इंडिया' का संपादन भी किया था। राममनोहर लोहिया ने शादी नहीं की और नहीं घर बसाया, क्योंकि उनका मानना था कि जिन्हें सार्वजनिक जीवन में जाना है, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। आज राजनीति परिवारवाद की महामारी को देखने से लगता है कि लोहियाजी या जान गए थे कि एक दिन यही सहोने वाला है, इसलिए इसे अभी र

ई नेताओं को आय से अधिक खर्च करने की आदत पड़ जाएगी तो देश

था-'पिछड़े पावें सौ में साठा' हालांकि जरा
वे ऊंची जातियों के विरोधी नहीं जी

यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप से तीसरे विश्व युद्ध का गहराता संकट और अंतरराष्ट्रीय कानून

रूस और यूक्रेन विवाद इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। रूस के आक्रामक रुख और यूक्रेन के खिलाफ हमले की अशंका ने विश्व में अशांति और असुरक्षा का परिवेश निर्मित किया है। वैश्विक पटल पर चिंता है कि यदि रूस यूक्रेन पर कोई सैन्य कार्रवाई या हमला करता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज जिस प्रकार के वैश्विक समीकरण बन रहे हैं, उससे यह भी स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर विभिन्न देशों में मतभेद है। ऐसे में इस मसले का समाधान तलाशने और इस भौगोलिक क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए।

पारोस्थातयों के आकलन से यह स्पष्ट है कि यूक्रेन पर रूसी हमले से नाटो का पूर्वी यूरोप में दखल और बढ़ जाएगा। साथ ही रूस दुनिया में अलग थलग होकर चीन पर और अधिक निर्भर हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह रूस के नाटो को पूर्वी यूरोप से दूर रखने के लक्ष्य पर कुठाराघात होने के साथ ही चीन के प्रति रूसी जनता, जो चीन को एक खतरे के रूप में देखती है, उसके भय को और बढ़ा देगा। इस संकट का लंबे समय से कायम यूरोप की स्थिता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि रूस यूक्रेन को न केवल नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है, अतिरिक्त यात्रा विरोध एवं रक्षा

हाता है कि मजूदा मसले का किस प्रकार निकल अंतर्राष्ट्रीय नून और संस्थाओं की इसमें क्या मेका हो सकती है देखा जाए तो युक्त राष्ट्र की मामले में वित्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। युक्त राष्ट्र शांति व व्यवस्था बनाए बन के लिए अपने मुख्य अंगों की याता से कार्य करता है व राष्ट्रों रा एक दूसरे की संप्रभुता व खंडों का सम्मान करना इसका अग्रणी सिद्धांत है। इस संदर्भ में युक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी सुरक्षा परिषद् सदैव कार्यरत ता है। विश्व में कहीं भी शांति उम्मेदन हो या होने की आशंका तो मामले का संज्ञान लेकर उचित वित्वपूर्ण मैं संस्थाएँ ताकि

यूक्रेन और रूस में जारी तनातनी को रोकने के लिए शांति के लिए पहल करे भारत

इस समय यूरोप शीत युद्ध के बाद सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। हालांकि यूक्रेन संकट 2014 से चल रहा है, परन्तु इस बार नाटो के विस्तार के बारे में नहीं है। एक तरफ रूस भारत का करीबी दोस्त है। घनिष्ठ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के अलावा भारतीय सशस्त्र बलों का लगभग 60 प्रतिशत हाईवैल्यर रूस से प्राप्त

भारत के चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं। भारत चीन को नियंत्रित करने के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विश्व का ध्यान आकर्षित करने में काफी सफल रहा है। लेकिन यूक्रेन संकट के कारण, सभी का ध्यान और संसाधनों को यूरोशिया की ओर मोड़ा जा रहा है। साथ ही, अगर भारत रूस के खिलाफ कोई पक्ष लेता है, तो आशंका है कि रूस चीन के साथ और करीब आ जाएगा। यह चीन के खिलाफ भारत के रणनीतिक प्रयासों को कमज़ोर कर सकता है। रूस प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने और अपने रक्षा-आदरयोगिक क्षेत्रों को चलाने के लिए पाकिस्तान को और अधिक हथियारों की आपूर्ति शुरू कर सकता है। यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिकों द्वारा यूरोपीय नेताओं ने बार-बार चेतावनी दी है कि यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के मामले में रूस को बड़े पैमाने पर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा और परोक्ष असर भारत पर भी पड़ेगा। जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने परमाण कार्यक्रम के कारण ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तो भारत पर भी ईरान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने का दबाव था। किसी भी गंभीर आर्थिक प्रतिबंध का प्रतिकार करने के लिए रूस तेल और गैस की आपूर्ति रोककर यूरोप को झटका दे सकता है। इसका असर भारत समेत पूर्व दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमत में और तेजी आ सकती है। ऐसे में यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है, तो भारत को रूस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थला करने के लिए अमेरिका से संभावित कूटनीतिक दबाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत इस बात ने भी परेशान है कि पश्चिमी देश द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध रूस के साथ उसके रक्षा व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि भारत को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप पसंद नहीं है और हमेशा दूसरे देश के मुद्दों पर तटस्था बनाए रखता है, लेकिन यूक्रेन संकट पर वह एक सूत्रधारी की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत के सभी पक्षों द्वारा साथ अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, भारत अपनी उभरती वैश्विक नेतृत्व भूमिका को देखते हुए अधिक योगदान दे सकता है। भारत पर नहीं लेगा, लेकिन कूटनीति को एक मौका देकर संबंधित पक्षों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की पहल कर सकता है।

प्रभाव रूसी क्षेत्र में बढ़ जाएगा। जिससे रूसी हितों व संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने धमकी दी है कि यदि युक्रेन नाटो में शामिल हुआ और पूर्वी यूरोप में तैनात नाटो सैनिकों की संख्या कम नहीं की गई तो रूस सैन्य कार्रवाई करेगा। उधर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर रूस को घेताया है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में रूसको को आर्थिक पाबंदियां व जवाबी कार्रवाई फ़ैलनी पड़ेगी। प्रथम दृष्टया इस संकट को कोई प्रत्यक्ष उत्तरकर नहीं है और यह संकट मुख्य रूप से अद्वितीय आंतरिक दबावों से उजाहुआ प्रतीत होता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का देश में राजनीतिक संस्थाओं व मीडिया पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना और रूस में राष्ट्रीयता की भावना के बढ़े? से रूस ने युक्रेन सहित कई पूर्वतरी सोवियत देशों में अपने हित साधने शुरू दिए हैं। रूसी सरकार पश्चिमी देशों को भी सदेह की दृष्टि से देखती है और उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाती रही है। पुतिन ने संभवतः पश्चिमी देशों की एकता में बिखराव व कमज़ोर नेतृत्व के चलते नाटो की शक्ति और निश्चय को परखने का यह सही समय चुना है। वर्तमान वैश्विक



समस्या का समाधान न केवल दोनों देशों के, बल्कि समस्त युरोपीय क्षेत्र व विश्व के हित में है। इस मामले को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है और अमेरिका सहित अन्य कई देश राजनीतिक हस्तक्षेप व कूटनीति से इस मामले का हल खोजने को प्रयासरत है। परंतु अभी इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में प्रश्न यह कि हो लेकर का पूर्व दो विश्व शांत है। कि को

देशों के मध्य संघर्ष की आशंका तो भी सुरक्षा परिषद को संज्ञान कर सदस्य देशों को उचित रवाई की संस्तुति करनी चाहिए। मैं अनेक बार ऐसा हुआ है कि या अधिक देशों के मध्य उपजे गढ़ को सुरक्षा परिषद ने वैश्विक तिव व सुरक्षा के लिए खतरा माना यहां तक कि अनेक मामलों में सी देश की आंतरिक अशांति भी वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रतिक्रिया अवश्य होगी। सुरक्षा परिषद व अन्य राष्ट्रों को भी प्रयास कर रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अपनी अपनी सेनाओं को सीमा से वापस बुला कर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं से क्षेत्र की निगरानी करनी चाहिए। इससे समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा और फिलहाल विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की आशंका दूर होगी।

